(ख) जी नहीं। तथापि, पोत लदान पूर्व निरीक्षण कार्य-विधियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अगर आवश्यक होता है तो उन्हें सरल और कारगर बनाया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गंगा और यमुना नदियों की सफाई

842. **श्री अश्विनी कुमार :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गंगा और यमुना नदियों की सफाई किये जने के अभियान के एक अंग के बतौर, किन-किन स्कीमों को स्वीकृति दी गई है अथवा किन-किन को स्वीकृति दी जानी है तथा ये परियोजनायें सफाई अभियान में किस हद तक योगदान करे रही हैं ;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिये आवंटित की गई धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आवंटित धनराशि में से अभी तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा सफाई कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) और (ख) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत मजूर की गई स्कीमों को 6 वर्गों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक वर्ग की स्कीमों की संख्या और उनकी अनुमानित लागत निम्नलिखित है :

विवरण	संख्या	लागत (रुपये करोड़)
—अपशिष्ट जल का अवरोधन और दिशा-परिवर्तन .	90	99.50
—सीवेज उपचार संयंत्र	32	105.08
—अल्प लागत स्वच्छता	42	20.40
—विद्युत शवदाहगृह	29	10.44
—शौचालयों और संबंधित सुधारों जैसी नदी तटाग्र सुविधाएं	34	13.47
—जलीय प्रजातियों के जैव संरक्षण नदी गुणवत्ता निगरानी (मानीटरिंग) जैसी अन्य स्कीमें . .	35	10.38
योग	262	259.27

गंगा कार्य योजना में यमुना नदी के लिये इलाहाबाद नगर के अलावा कोई स्कीम शामिल नहीं है। इलाहाबाद में ही नगर के मल-जल का पर्याप्त भाग संगम से पहले यमुना नदी में प्रवाहित होता है। गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद के लिए इस अपशिष्ट जल के अवरोधन और दिशा परिवर्तन की स्कीमें पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। अधिकांश स्कीमें सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान पूरी हो जायेंगी और कुछ आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान भी चलेंगी। इसके बाद ही नदी गुणवत्ता का मूल्यांकन हो सकेगा।

(ग) गंगा कार्य योजना के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के

दौरान 240 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित है। आज तक इस योजना के अन्तर्गत लगभग 86 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं। अभी तक 26 स्कीमें पूरी हो चुकी है। शेष अधिकाश संस्वीकृत स्कीमों में कार्य प्रगति पर है। इनमें से 164 स्कीमों के अभी और सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

843. [*Transferred to the 12th August*, 1988]

Maharashtra-Karnataka Border Disputes

844. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what steps have been taken by the Central Government during the last three years to solve the long-standing border dispute between Maharashtra and Karnataka; and

(b) what is Central Government's reaction to the recent suggestion made by the Chief Minister of Maharashtra to resolve the issue by referendum in the disputed border areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) and (b) The Government of India have always been of the view that this dispute can be resolved only with the willing cooperation of the State Governments concerned. The Central Government remain in touch with both the State Governments in the matter Central assistance as required for arriving at a mutually acceptable solution to this problem will be rendered.

Setting up of a Jewellery Export Centre at Ahmedabad

845. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to set up a Jewellery Export Centre at Ahmedabad;

(b) if so, what steps have been taken in this regard; and

(c) by when the Centre is likely to be set up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) to (c) A request has been received to set up an export oriented jewellery manufacturing complex at Ahmedabad (Gujarat). The State Government has been requested to identify suitable sponsoring agencies and building premises.

Credit-Deposit Ratio of States

846. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is gap in credit-deposit ratio of different States in the country;

(b) what are the details of credit-deposit ratio of different States during the last three years, year-wise;

(c) whether it is a fact that the credit amount is less than the deposit amount in the case of Gujarat; and

(d) if so, what steps Government are taking to increase the credit amount of Gujarat?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) State-wise credit:deposit ratio of all scheduled commercial banks as on the last Friday of December 1985, 1986 and 1987 are set out in the attached Statement (*See* below) Deployment of credit out of the locally mobilised deposits in a particular area/region depends upon the requirement of credit and the level of economic activities which